अनुलग्नक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- महात्मा गांधी नरेगा के तहत बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बजट आवंटन 11,300 करोड़ रुपये था जो 2013-14 में बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये हो गया और अब वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 86,000 करोड़ रुपये है।

- योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों पर उपलब्धि निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	**2006-07** से **2013-14**	**2014-15** से **2024-25** **(18.03.25** तक)
1	कुल सृजित श्रमदिवस [करोड़ में]	1,660	3,029
2	रिलीज की गई केंद्रीय निधि [रु. करोड़ में]	2,13,220	7,81,302
3	पूर्ण कार्यों की संख्या (लाख में)	153	807

- महिलाओं की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 48% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 58.19% हो गई है।

- इस योजना में कई सूचना प्रद्योगिकी पहल की गई हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगभग 97.81% फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) समय पर तैयार किए गए हैं, जिससे मजदूरों को ससमय मजदूरी भुगतान सुनिश्चित हो रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में (अब तक) 86.98 लाख से अधिक उपयोगी परिसंपतियों का निर्माण किया जा चुका है, जो ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

- वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन 17.6% था जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में (18.03.25 तक) बढ़कर 56.99% हो गया है ।

- कुल व्यय का लगभग 44.14% कृषि और सबंधित गतिविधियों पर खर्च किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

-
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) और कृषि संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन से जल की कमी वाले प्रखंडों की संख्या में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ऐसे प्रखंडों की संख्या 2,264 से घटकर 1,456 हो गई है । यह उपलब्धि पानी की कमी से जल सुरक्षा की सफलता को दर्शाता है।

  - अब तक, लगभग 97% सक्रिय श्रमिक आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली से जुड़ चुके हैं।

  - योजना के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों का जियोटैग किया गया है। अब तक 6.26 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का जियोटैग किया जा चुका है।

- राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली(NMMS) ऐप: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी कार्य स्थलों पर (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना/परियोजना को छोड़कर) लाभार्थियों की दिन में दो बार जियो-टैग की गई तस्वीर के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने और उसे पब्लिक डोमेन में डालने का प्रावधान शुरू किया गया है जिससे तेजी से भुगतान करने में पर्याप्त सहायता मिलने के अलावा इस कार्यक्रम की नागरिकों द्वारा निगरानी में वृद्धि होती है।
- NRSC-ISRO द्वारा युक्तधारा पोर्टल विकसित किया गया है जिसका उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र एवं वैज्ञानिक तरीके से GIS-आधारित कार्यों का चयन किया जाना है । युक्तधारा पोर्टल का बेहतर उपयोग हेतु क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- इस मंत्रालय ने अनेक सुशासन पहलों, जैसे कि जॉब कार्ड सत्यापन/अद्यतनीकरण, 22 (बाइस) रजिस्टरों के स्थान पर 7 (सात) रजिस्टरों को अपनाना, सामाजिक लेखा परीक्षा औरआंतरिक लेखा परीक्षा पर जोर देना, आजीविका के लिए दिहाड़ी श्रम पर निर्भर भूमिहीन परिवारों को सक्रिय रूप से शामिल करना, नागरिक सूचना बोर्डआदि।

- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 13 मंत्रालयों के साथ अभिसरण पहल, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण और सीमा सड़क संगठन के साथ अभिसरण में सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क प्रदान करना शामिल है।

- मिशन अमृत सरोवर: अब तक, 68,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार पूरा हो चुका है। अमृतसरोवर के रूप में जल निकायों के निर्माण और कायाकल्प के लिए मिशन को जारी रखा जाना है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वि.व. 2013-14	वि.व. 2024-25 (18.03.25 की स्थिति के अनुसार)
1	महिला भागीदारी	48%	58.19%
2	नरेगासॉफ्ट में आधार सीडिंग (सक्रिय कामगार)	जनवरी, 2014 में 76 लाख	13.45 करोड़
3	आधार भुगतान सेतु प्रणाली (एपीबीएस) पर कामगार (सक्रिय कामगार)	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	13.05 करोड़
4	महात्मा गांधी नरेगा योजना परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	पब्लिक डोमेन में 6.26 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियां जिया-टैग की जा चुकी हैं।
5	ईएफएमएस के माध्यम से मजदूरी के भुगतान (ई-भुगतानों) की स्थिति	37%	99.94%
6	एनईएफएमएस (सीधे कामगारों के खातों में मजदूरी)	उपलब्ध नहीं	27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित
7	ग्राम पंचायत स्तर पर रजिस्टरों की संख्या कम करना	महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर औसतन 22.29 रजिस्टर रखे जाते थे।	इन रजिस्टरों की संख्या कम करके केवल 7 सरलीकृत रजिस्टर रखे गए हैं; अब तक 2.50 लाख ग्राम पंचायतों ने ये रजिस्टर अपना लिए हैं।
8	व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण	17.6%	56.99%
9	सिक्योर (सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	फिलहाल 28 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 703 जिलों में कार्यान्वित

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वि.व. 2013-14	वि.व. 2024-25 (18.03.25 की स्थिति के अनुसार)
	यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लाइमेंट)		
10	क्लस्टर फेसिलिटेशन प्रोजेक्ट (सीएफपी)	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	यह 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य 108 आकांक्षात्मक जिलों के 231 ब्लॉकों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के 46 ब्लॉकों में महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है, ताकि बेहतर योजना, निगरानी और समन्वय के माध्यम से विकास को तेज किया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों को प्रदान किया जाएगा।
11	उन्नति परियोजना (लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशलों का उन्नयन करने के उद्देश्य से)	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	दिसम्बर, 2019 में शुरू की गई। उन्नति परियोजना 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी है। अब तक लगभग 83,970 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
12	राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	21मई, 2021 में लॉन्च किया गया। यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति को जियो-टैग किए गए फोटो के साथ लेने की अनुमति देता है।
13	एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग ऐप	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	21मई, 2021 में लॉन्च किया गया। यह ऐप राज्य सरकार के

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वि.व. 2013-14	वि.व. 2024-25 (18.03.25 की स्थिति के अनुसार)
			अधिकारियों को किसी भी कार्य की सुचारू निगरानी करने और निष्कर्षों को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।
14	हरित ऊर्जा-बायो गैस संयंत्र	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के परिवार के लिए बायो गैस संयंत्र के निर्माण की अनुमति दे दी गई है।